

हमारा दुश्मन कोई नहीं होता क्योंकि हम खुद के दुश्मन बनकर अपना नुकसान कर जाते हैं।
- अज्ञात

अतीत की ओर मुड़कर देखना

हम पुरानी चीजों की आज से तुलना कर वर्तमान उपलब्धियों को रेखांकित कर सकते हैं। रामायण, महाभारत जैसे धारावाहिक आज चालीस पार पहुंचे लोगों के लिए नॉस्टैल्जिया का विषय होंगे, लेकिन नई पीढ़ी उन्हें कौतूहल से ही देखेगी।

ललिता शर्मा।

लॉकडाउन के कारण घरों में बंद लोगों के लिए सरकार ने मनोरंजन का एक रोचक रास्ता खोजा है। उसने दूरदर्शन पर 80 और 90 के दशक के कुछ पुराने धारावाहिकों को फिर से दिखाना शुरू किया है। ये वे धारावाहिक हैं, जिन्होंने अपने जमाने में लोगों को काफी प्रभावित किया था और आज भी उन्हें याद किया जाता है। ये धारावाहिक हैं— रामायण, महाभारत, सर्कस और व्योमकेश बख्शी।

संकट के इस दौर में अतीत की ओर मुड़कर देखने का यह नुस्खा कुछ अटपटा लग सकता है, लेकिन जब भविष्य को लेकर सामने धुंधलापन हो तो अतीत की ओर देखना सहज मानवीय प्रवृत्ति है। अक्सर किसी संकट के समय हम पुराने दिनों को याद कर राहत महसूस करते

हैं। संभव है पुराने धारावाहिक भी लोगों को कुछ राहत पहुंचाएं। हालांकि, जिस समय ये धारावाहिक बने, उस समय से लेकर आज तक तकनीक के क्षेत्र में काफी बदलाव हुए हैं। मनोरंजन उद्योग का दायरा काफी बढ़ गया है। टीवी के समानांतर न जाने कितने प्लैटफॉर्म आ गए हैं, जिन पर हम मनोरंजन करते हैं। बहरहाल, बदलाव की यह प्रक्रिया भी पुरानी चीजों को देखते हुए हमारे भीतर नए सिरों से दर्ज होगी। हम पुरानी चीजों की आज से तुलना कर वर्तमान उपलब्धियों को रेखांकित कर सकते हैं। रामायण, महाभारत जैसे धारावाहिक आज चालीस पार पहुंचे लोगों के लिए नॉस्टैल्जिया का विषय होंगे, लेकिन नई पीढ़ी उन्हें कौतूहल से ही देखेगी।

तमाम तरह की अत्याधुनिक तकनीकों के

बीच आंख खोलने वाली जेनरेशन को वे धारावाहिक फीके लग सकते हैं जिस तरह पुरानी फिल्में लगती हैं। हालांकि इनके जरिए वे भारतीय मिथकों और पौराणिकता को बेहतर समझ सकते हैं। जैसे जब अतीत में लौटना ही था तो बेहतर होता कि एकदम आरंभिक सोप ऑपेरा दिखाए जाते। आज 'हमलोग' जैसे शुरुआती दौर के पॉपुलर सीरियल देखना एक विशिष्ट अनुभव होता।

हम परख सकते थे कि आखिर इनमें कौन सी ऐसी बात थी जिसने उस वक्त लोगों को इतना छुआ। संभव हो तो 'बुनियाद' जैसा धारावाहिक दिखाया जाए। वैसे 'सर्कस' और 'व्योमकेश बख्शी' जैसे धारावाहिक हमारे भीतर यह सवाल भी पैदा कर सकते हैं कि आखिर आज के धारावाहिक तमाम तरह की तकनीक और

साधन संपन्नता के बावजूद कंटेंट के स्तर पर ज्यादातर खोखले क्यों नजर आते हैं? क्यों चार-पांच एपिसोड के बाद वे थकने से लगते हैं? आज से तीस साल पहले जब इतने मजबूत कथ्य वाले धारावाहिक बन सकते थे तो आज क्यों नहीं। आखिर आज साहित्यिक कृतियों पर 'मालगुडी डेज', 'नीम का पेड़', 'काला जल' और 'कर्मभूमि' जैसे धारावाहिक क्यों नहीं बन सकते? आखिर बाधा कहां है? वैसे अतीत दर्शन का एक खतरा यह भी है कि कहीं वह हमारे जेहन को जकड़ न ले। हम मानसिक रूप से वहीं थम न जाएं। हमें वापस लौटने की गुंजाइश बनाए रखनी होगी। हमें रिटर्न टिकट रखे रहना होगा। अतीत से कुछ न कुछ सबक लेकर आना होगा और फिर भविष्य की तैयारी में जुट जाना होगा।

आज्ञाकारी

अशोक वोहरा।

माता-पिता यह कर लेते हैं कि बच्चे को पूरी तरह आज्ञाकारी बनना है। उनके अनुसार आज्ञाकारी बच्चा ही सम्मान पाता है। लेकिन इतना निहित है कि आप उसे पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। उसकी उम्र बढ़ती जायेगी मगर उसका विकास नहीं होगा। वह बड़ा होगा पर उसमें फूल नहीं लगेगे, फल नहीं होगा। वह जीवित रहेगा लेकिन उसके जीवन में थिरकना नहीं होगा, गीत नहीं होगा, हसौल्लास नहीं होगा। आपने वो सभी आधारभूत संभावनाएं नष्ट कर दी हैं जो एक आदमी को व्यक्तिगत, सच्चा, ईमानदार बनाता है और उसे एक निश्चित पूर्णता देता है। और यही सब वह है जो एक आज्ञाकारी व्यक्ति करता है। यह अपंगता है कि आप ना नहीं कह सकते और आपको सिर्फ हां कहना है। पर एक आदमी जब ना कहने में असमर्थ हो जाता है तो उसका हां कहना अर्थहीन हो जाता है।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

सबके अपने दावे

कोरोना महामारी से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को जबर्दस्त झटका लगा है। वास्तविकता यह है कि आज यूरोप, चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था से सभी देशों की इकॉनमी जुड़ी हुई है। किसी एक के प्रभावित होने से दूसरे पर भी संकट आ जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई है और आने वाले दौर में तीसरे पायदान पर पहुंचने का लक्ष्य रख कर आगे बढ़ रही है। कोरोना की आपदा ने पहले चीन को झटका दिया। पर चूंकि वहां प्रजातंत्र नहीं है और सरकार का जबर्दस्त डंडा चलता है तो उसने डंडे के जोर पर इस महामारी को रोक लिया। जैसी जानकारी मिल रही है वहां आर्थिक गतिविधियां फिर से चालू हो रही हैं, जिसके कारण यह आशंका पूरे विश्व में फैल रही है कि दुनिया को सही समय पर इस त्रासदी की सूचना चीन की तरफ से नहीं मिली।

यूरोप, खासकर इटली और स्पेन में महामारी बड़े पैमाने पर फैल गई है। वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और ये देश अपने आप को विवश महसूस कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी मानी जाती हैं। अमेरिका में अभी देखना पड़ेगा कि वह कैसे और कितना इससे जूझने में सफल होता है। भारत में भी यह महामारी लगातार अपने पांव पसार रही है। हम इसे किस तरह और कितना संभाल पाते हैं, यह तो आने वाला समय बताएगा। इस मायने में अगले 20 दिन महत्वपूर्ण हैं। अभी यह उत्सुकता का विषय है कि हम इस महामारी को जन भागीदारी और प्रबल इच्छा शक्ति से किस हद तक रोक लेते हैं। अगर हम इस पर काबू नहीं कर पाए तो यह भारत की अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख देगी।

फिर सवाल उठ कि जो रास्ते में हैं, वे खाएंगे क्या। फिर जिला प्रशासन, रेलवे, पुलिस और गैर सरकारी संगठनों ने जगह-जगह उनके खाने की व्यवस्था शुरू की।

सामाजिक-आर्थिक सवाल

नरेंद्र नाथ

कोरोना वायरस से लड़ाई के क्रम में देश को एक नई समस्या से जूझना पड़ रहा है। वह है राजधानी समेत तमाम छोटे-बड़े शहरों से मजदूरों का पलायन। खासकर दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बड़ी संख्या में कारखाना मजदूर और दिहाड़ी कामगार बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थित अपने गांवों की ओर पैदल ही निकल पड़े हैं। इस अप्रत्याशित स्थिति का देश के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी को रती भर अंदाजा नहीं था। लॉकडाउन की स्थिति में झुंड बनाकर चल रहे इन मेहनतकशों की तस्वीरों ने देश के सामने कुछ गहरे सामाजिक-आर्थिक सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा 21 दिनों तक घर से बाहर आवाजाही पर रोक की घोषणा किए जाने के साथ ही ये मजदूर अपने ठिकानों से निकल पड़े। उनका यह हाल देखकर चौकन्नी हुई सरकार ने एक के बाद एक घोषणाओं की झड़ी लगा दी। पहले कहा गया कि उन्हें बेहद कम दरों पर राशन मिलेगा, सीधे उनके खाते में पैसे भेजे जाएंगे। फिर सवाल उठा कि जो रास्ते में हैं, वे खाएंगे क्या। फिर जिला प्रशासन, रेलवे, पुलिस और गैर सरकारी संगठनों ने जगह-जगह उनके खाने की व्यवस्था शुरू की। कुछ बस



सेवाएं भी शुरू की गईं ताकि वे अपने गांव जा सकें। लेकिन इसके बावजूद मामला सुलझ नहीं रहा। बात सिर्फ इनके रहने-खाने और कहीं जाने की नहीं है। उनमें से कितने लोग संक्रमण के शिकार हैं, कोई नहीं जानता।

हजार में एक केस भी अगर ऐसा निकल गया तो बीमारी गांव-गांव में फैल जाएगी। अभी तक माना जा रहा था कि कोरोना का प्रकोप शहरों तक सीमित है, लेकिन मजदूरों के पलायन से इसका दायरा बहुत बढ़ जाने का खतरा है। इसी

उर से लोगबाग बाहर से आए अपने ही लोगों को गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। इसे लेकर कई जगह झगड़े हो चुके हैं। राज्य सरकारों की ओर से अपील की जा रही है कि वे जहां हैं, वहीं रुक जाएं पर वे नहीं रुक रहे। मान लीजिए, रुक भी गए तो क्या उन्हें ठहराने का पर्याप्त इंतजाम है? केंद्र सरकार का स्पष्ट आदेश ऐसे हर व्यक्ति को फिलहाल चौदह दिन के क्वारंटीन में रखने का है। इस दौरान न सिर्फ उनके ठहरने का बल्कि सबको एक-दूसरे से दूर रखने का भी इंतजाम करना होगा। उनके खानपान और किसी बीमारी की स्थिति में दवा की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही कोरोना के लिए उनका टेस्ट भी करना होगा। किसी में वायरस पाया गया तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना होगा और उस कैंप में मौजूद हर व्यक्ति को संक्रामक बीमारी का संभावित मरीज मानकर उस पर खास नजर रखनी होगी।

अभी जैसे दबाव का सामना सरकारी मशीनरी कर रही है, उसके बीच क्या यह सब संभव है? सड़क पर निकले इन लोगों में से ज्यादातर यूपी-बिहार के हैं। पुलिस और चिकित्साकर्मियों की संख्या इन दोनों राज्यों में हमेशा ही जरूरत से कम मानी जाती रही है। ऐसे में दोनों राज्यों का पूरा तंत्र इन्हीं की देखरेख में जुटा रहेगा तो कोरोना से निपटने के राष्ट्रव्यापी कार्यभार का क्या होगा?

सूडोकू नववाला-5306				सूडोकू नववाला-5305 का हल			
3		8		9			
	8	6		9	5		
6	5		4		7	1	
						2	
1	2		6		9	8	
		6	4		5	8	
9				1			7

अपना ब्लॉग

चुनौतियों पर नजर

मोहन। भारत सरकार जिस तरह से अब सोच रही है, उस पर जल्द ही और आगे बढ़ेगी तो हमारे मैनुफैक्चरिंग उद्योगों को बड़ा सहारा मिलेगा। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम भी विश्व में काफी गिर गए हैं जिससे भारत को बड़ी राजकोषीय राहत मिल रही है। अभी आवश्यकता है सबसे कमजोर वर्ग को राहत देने की। दिहाड़ी मजदूरों, रेहड़ी लगाने वालों और असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मियों को आने वाले एक-दो महीने के भीतर सीधे धन उपलब्ध कराना होगा। यह आवश्यक है कि उन्हें कुछ नियमित आमदनी होती रहे। कामकाज बंद होने से उन्हें जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई आवश्यक है। इसलिए जब तक उनकी व्यवस्थित कमाई की शुरुआत न हो तब तक उनके खाते में पैसे पहुंचते रहने चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है और सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया है। इसलिए यह जरूरी है कि इन 21 दिनों की विकट परिस्थिति में हम अपना धैर्य न खोएं।

2022 तक अंतरिक्ष में मानव भेजने की योजना: ओडी

...और शुरुआत
उन्से हो जिनका नाम
नागरिकता रजिस्टर
में नहीं है.

